1

1.1	वैश्विक व्यापक वित्तीय परिस्थितियां
1.2	घरेलू व्यापक आर्थिक प्रगति
1.3	कृषि ने दर्शाई अनियमित वर्षा क्रम के प्रति अनुकूलता
1.4	ग्रामीण आर्थिक गतिविधि में आई गति
1.5	आर्थिक दृष्टिकोण
	अध्याय 1 का परिशिष्ट

भारत और विश्व
वित्तीय वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था

मुद्रास्फीति में नरमी, टिकाऊ बाह्य संतुलन की स्थिति, वित्तीय स्थिरता, कॉर्पोरेटों के स्वस्थ तुलन-पत्रों, व्यवस्थित वित्तीय बाज़ारों और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में निरंतर सुधारों के चलते विकास की गति उम्मीद से भी अधिक रही.

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष के दौरान नरमी का अनुभव किया क्योंकि क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति में भी कमी आई. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को आक्रामक रूप से सख्त किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान आशंकित वैश्विक मंदी को टाला जा सका. वैश्विक खाद्यान्नों और वस्तुओं की कीमतों में गिरावट और आपूर्ति श्रृंखला की रुकावटों को कम करने से इसमें सहायता हुई. फिर भी वैश्विक व्यापक आर्थिक वातावरण भू-आर्थिक विखंडनों, ऋण के उच्च स्तरों और जलवायु संबंधी घटनाओं के बढ़ते जोखिमों के प्रभाव से संतप्त ही रहा जिससे कोविड-19 महामारी से पहले की प्रवृत्ति की तुलना में कम-से-कम मध्यावधि विकास की संभावनाओं को तो कम ही कर दिया.

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक झटकों के प्रति उल्लेखनीय अनुकूलता दर्शाई और मजबूत विकास दर दर्ज की – मुद्रास्फीति में नरमी, टिकाऊ बाह्य संतुलन की स्थिति, वित्तीय स्थिरता, कॉरपोरेटों के स्वस्थ तुलन-पत्रों, व्यवस्थित वित्तीय बाज़ारों और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में निरंतर सुधारों के चलते, वित्तीय वर्ष 2024[1] के दौरान वास्तविक विकास की गति उम्मीदों से भी अधिक थी. निरंतर सुधारों के परिप्रेक्ष्य में, निवेश आधारित विकास की प्रक्रिया और मजबूत व्यापक नीतिगत व्यवस्था से विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की बढ़त को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है.

1.1 वैश्विक व्यापक वित्तीय परिस्थितियां

वैश्विक विकास की गति ने ब्याज की उच्च दरों के प्रति उम्मीद से अधिक अनुकूलता का प्रदर्शन किया जो पूरे वर्ष बनी रही साथ ही केंद्रीय बैंकों ने निर्वाह व्यय के संकट को प्रबंधित करने पर अपना नीतिगत ध्यान बनाए रखा. आपूर्ति श्रृंखला के दबावों में कमी, श्रमबल भागीदारी में सुधार और वैश्विक खाद्य कीमतों में निरंतर गिरावट के कारण आपूर्ति पक्ष के विस्तार ने लचीलापन प्रदान किया. नतीजतन, आशंकित वैश्विक मंदी, जो आमतौर पर समकालिक वैश्विक मौद्रिक कसाव के एक आक्रामक चरण का परिणाम होती है, से बचा जा सका. वर्ष 2023 में 3.3% की वैश्विक विकास दर, वर्ष 2022 में दर्ज 3.5% की तुलना में मामूली रूप से धीमी रही (तालिका 1.1).

वर्ष 2022 में शिखर पर पहुंच चुकी वैश्विक समेकित मुद्रास्फीति, वर्ष के दौरान नरम होती गई, किंतु केंद्रीय बैंकों के अपने-अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों से ऊपर ही मँडराती रही, जिससे मुद्रास्फीति कम करने का अंतिम पड़ाव उनके लिए एक कठिन चुनौती बना रहा. मौद्रिक नीति में नरमी आने के चरण की शुरुआत के समय बाजार की उम्मीदों और भविष्य के ब्याज दर रुझानों से संबंधित धारणाओं ने वित्तीय बाज़ारों को प्रभावित किया, जिससे प्रतिफल और पैदावार और टर्म प्रीमिया अस्थिर बने रहे. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अनुमानित मुद्रास्फीति वर्ष 2024 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय रूप से कम होगी जबकि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह यथावत् बनी रह सकती है (तालिका 1.1). वस्तुओं, तेल और गैर-तेल दोनों, की कीमतों में कमी, जो वर्ष 2022 में उछाल पर थीं, उनमें वर्ष 2023 के दौरान ठहराव आया और वर्ष 2024 में इनकी कीमतों में आंशिक कमी आने की संभावना है.

वैश्विक वस्तु व्यापार में वर्ष 2023 में 1.2% की गिरावट आई; वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार (एक साथ लिया गया) में भी 0.8% की धीमी वृद्धि दर्ज हुई.[2] आईएमएफ के अनुसार, वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में देशों द्वारा व्यापार पर क्रमश: लगभग 3,200 और 3,000 नए प्रतिबंध लगाए गए. यूएनसीटीएडी के अनुसार वर्ष 2023 में, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 9% की गिरावट आई है.[3] इस प्रकार, व्यापार और निवेश में वृद्धि के चैनल मंद बने रहे, जो आंशिक रूप से भू-आर्थिक विखंडन के प्रभाव को परिलक्षित करते हैं.

तालिका 1.1: वैश्विक आर्थिक संकेतक (वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत वृद्धि)

विवरण	*2022*	*2023*	*2024*
विश्व उपलब्धि	3.5	3.3	3.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (एई)	2.6	1.7	1.7
उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई)	4.1	4.4	4.3
विश्व व्यापार परिमाण (वस्तु और सेवाएं)	5.6	0.8	3.1
विश्व व्यापार परिमाण (वस्तुएं)*	3.0	-1.2	2.6
विश्व उपभोक्ता मूल्य	8.7	6.7	5.9
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	7.3	4.6	2.7
उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	9.8	8.3	8.2
वस्तु मूल्य			
तेल	39.2	-16.4	0.8
गैर-तेल	7.9	-5.7	5.0

स्रोत:

- आईएमएफ (2024), वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जुलाई 2024, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंग्टन डी.सी. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/07/16/world-economic-outlook-update-july-2024.
- वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम (गूड्स): डब्ल्यूटीओ (2024) ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एण्ड स्टैटिस्टिक्स, अप्रैल 2024, विश्व व्यापार संगठन, जिनीवा, स्विट्जरलैंड. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_outlook24_e.pdf.

1.2 घरेलू व्यापक आर्थिक प्रगति

1.2.1 व्यापक स्थिरता के साथ स्वस्थ वृद्

वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकट विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर में अधिक तेजी आई और उसने लगातार तीसरे वर्ष 7% या उससे अधिक की वृद्धि दर दर्ज की (चित्र 1.1). जैसा कि आर्थिक गतिविधि संकेतकों ने वर्ष के दौरान विकास की गति के अधिक मजबूत होने के संकेत दिए गए थे, वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सकल घरेलू

चित्र 1.1: 2011-12 के मूल्यों पर भारत के जीडीपी वृद्धि के रुझान (%)

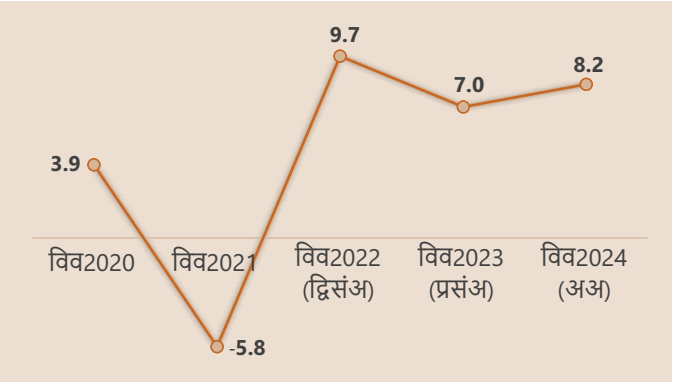

प्रसंअ = प्रथम संशोधित अनुमान, जीडीपी = सकल घरेलू उत्पाद, अअ = अनंतिम अनुमान, द्विसंअ = द्वितीय संशोधित अनुमान.
स्रोत: भारत सरकार (2024), राष्ट्रीय आय वित्तीय वर्ष 2024 के द्वितीय अग्रिम अनुमान, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. https://www.mospi.gov.in/sites/ default/files/press_release/PressNoteGDP31052024.pdf.

वित्तीय वर्ष 2024 में औसत मुद्रास्फीति घटकर 5.4% हो गई, जो सरकार द्वारा अग्रसक्रिय रूप से किए गए मौद्रिक नीति को कड़ी करने के और लक्ष्योन्मुखी आपूर्ति पक्षीय उपायों को दर्शाती है.

उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि को 7.3% (प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार) से 7.6% (द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार) और आगे 8.2% (अनंतिम अनुमानों के अनुसार) तक संशोधित किया गया था. पूंजीगत व्यय पर राजकोषीय नीति के निरंतर बल दिए जाने के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2024 में निवेश में स्वस्थ (9%) वृद्धि (यानी, सकल अचल पूंजी निर्माण में वृद्धि) के कारण विकास की गति में तेज़ी आई. अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक क्षेत्रों में, निर्माण और विनिर्माण ने 9.9% की उच्चतर वृद्धि दर्ज की.[4]

1.2.2 अग्रसक्रिय मौद्रिक और आपूर्ति प्रबंधन उपायों के कारण मुद्रास्फीति में कमी

वित्तीय वर्ष 2023 में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति बढ़कर 6.7% हो गई, जो मुद्रास्फीति लक्ष्य के उच्चतम सह्यता मानदंड (बैंड) से भी ऊपर थी, क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध के करण हुए आपूर्ति व्यवधान की वजह से वैश्विक खाद्यान्नों और ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई थीं (चित्र 1.2). हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024 में औसत मुद्रास्फीति घटकर 5.4% हो गई और वर्ष के अंतिम 4 महीनों के दौरान मूल (खाद्यान्नों और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति 4% से भी कम हो गई, जो यह दर्शाता है कि:[5]

- नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों (मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच) की संचयी वृद्धि के रूप में, अग्रसक्रिय रूप से मौद्रिक नीति को कड़ा किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2024 और उसके बाद भी बना रहा; और
- सरकार द्वारा निम्नलिखित के रूप में आपूर्ति पक्ष पर किए गए लक्ष्योन्मुखी उपाय :
  - घरेलू उपलब्धता में सुधार के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाना,
  - पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करना,
  - बफर स्टॉक से खाद्यान्नों को बाज़ार में उतारना,
  - कुछ आयातित खाद्य मदों की लागत को कम करने के लिए शुल्क कम करना, और
  - इथेनॉल आदि के उत्पादन के लिए गन्ने के शीरे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना.

चित्र 1.2: भारत में उपभेक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का वार्षिक औसत (%)

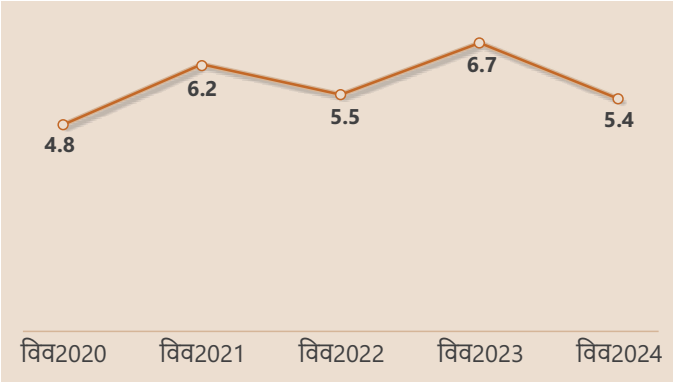

स्रोत:

1. भातर सरकार (विभिन्न वर्ष), केंद्रीय संख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.
2. आरबीआई (2024), मौद्रिक नीति विवरण (2023–24), भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई.

1.2.3 व्यापक स्थिरता के साथ वृद्धि करने के लिए वित्तीय सुदृढ़ीकरण और उच्चतर सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी व्यय

महामारी के गंभीर, व्यापक आर्थिक प्रभावों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक राजकोषीय नीतिगत प्रतिक्रिया को प्रतिबिंबित करते हुए, केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), वित्तीय वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% (और केंद्र और राज्यों का समेकित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 13.3% तक) पहुंच गया था.

चित्र 1.3: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा और पूंजीगत व्यय

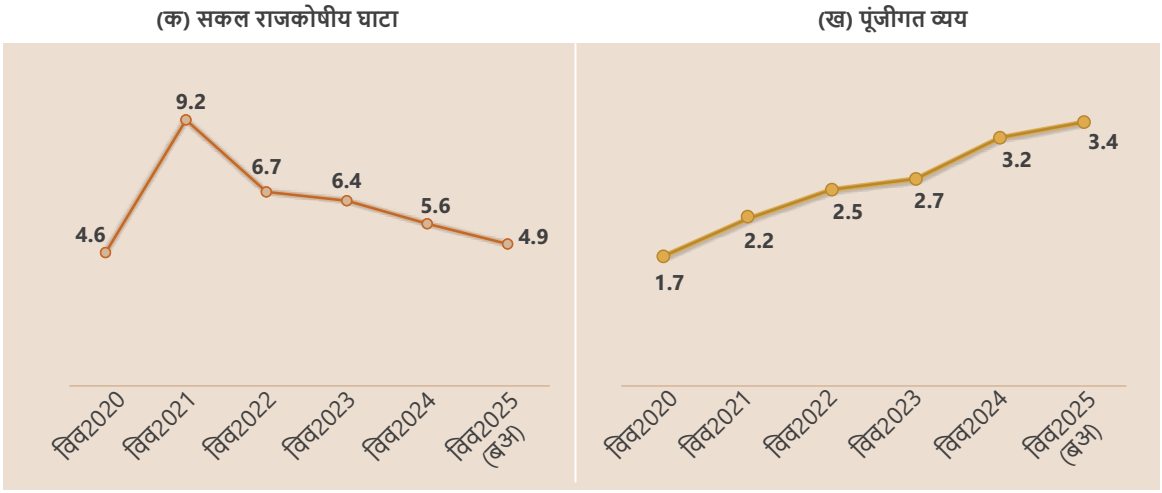

बअ = बजट अनुमान, जीडीपी = सकल घरेलू उत्पाद.

स्रोत: केंद्रीय बजट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.

तब से, राजकोषीय नीति का रुख पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए अधिक आबंटन के साथ-साथ क्रमिक समेकन के लिए दृढ़ होता गया. जिससे गैर-मुद्रास्फीतिजन्य वृद्धि को बढ़ावा मिलने लगा. वित्तीय वर्ष 2025 के अंतरिम बजट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जीडीपी के 5.6% के जीएफडी (अनंतिम अनुमान) को 5.9% के बजट अनुमान से कम रखा गया है और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बजट में जीएफडी को बाज़ार की अपेक्षाओं से कम 4.9% रखा गया है. वित्तीय वर्ष 2026 तक जीएफडी को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से भी कम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई. महामारी के बाद की बहाली को चलाते रहने और विकास की गति में तेजी लाने के लिए कैपेक्स पर जोर देते हुए, वित्त वर्ष 2025 के लिए बजट में कैपेक्स का हिस्सा बढ़ाते हुए सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% रखा गया है (चित्र 1.3 क और ख). राज्यों के जीएफडी के, वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी के 4.1% से घटकर वित्तीय वर्ष 2024 में जीडीपी के 3.1% होने के साथ (बजट अनुमानों के अनुसार), समेकित घाटा भी घटकर जीडीपी का 7% हो गया.[6]

1.2.4 बाह्य शेष की स्थिति संधारणीय बनी रही

एक प्रतिकूल वैश्विक वातावरण में, विश्व व्यापार में धीमी वृद्धि और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की सख्त मौद्रिक नीति के रुख के कारण बढ़े हुए परिणामी जोखिमों के बीच, भारत की भेद्यताएं चालू खाता घाटे (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) के पिछले वर्ष की तुलना में कम होने

चित्र 1.4: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता घाटा

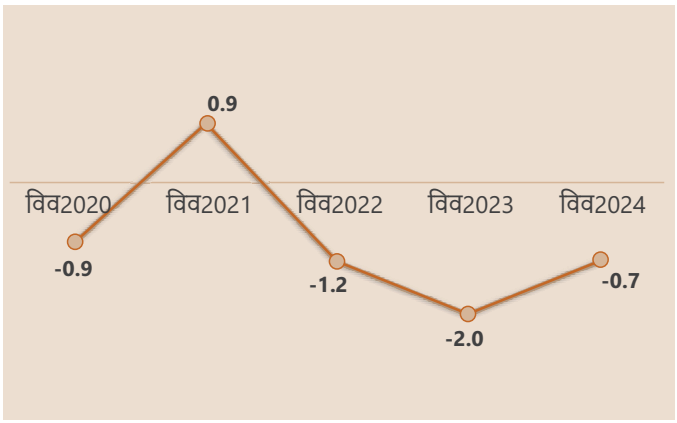

जीडीपी = सकल घरेलू उत्पाद.

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, भारतीय रिज़र्व बैंक. https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home.

जलवायु संबंधी झटकों के प्रति भारतीय कृषि के बढ़ते लचीलेपन के साथ कृषि क्षेत्र का जीवीए कुछ वर्षों से निरंतर बढ़ता जा रहा है.

और व्यापार घाटे के परिप्रेक्ष्य में संधारणीय स्तरों तक बने रहने के कारण और सेवाओं के निर्यात और धनप्रेषणों के माध्यम से अधिक प्राप्तियों के कारण नियंत्रित रहीं और पोर्टफोलियो प्रवाह में एक बदलाव (चित्र 1.4) आया. जनवरी-मार्च 2024 में, शेष राशि के भुगतानों में चालू खाते में सकल घरेलू उत्पाद के 0.6% के बराबर का अधिशेष दर्ज किया गया. वित्त वर्ष 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $646.4 बिलियन हो गया.[7]

1.3 कृषि ने दर्शाई अनियमित वर्षाक्रम के प्रति अनुकूलता

दक्षिण-पश्चिमी मानसून की वर्षा ने वर्ष का अंत 5.6% की कमी (लंबी अवधि की औसत वर्षा की तुलना में) के साथ किया, और वर्षापात का वितरण भी अनिश्चित था, जहां वर्ष 2023 के जून और अगस्त में कम वर्षा हुई वहीं वर्ष 2023 के जुलाई और सितंबर में आवश्यकता से अधिक वर्षा का सामना करना पड़ा.[8] वर्षा का भौगोलिक वितरण भी असमान था, पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों और दक्षिणी प्रायद्वीप में कम वर्षा हुई. खरीफ की उपज पर प्रतिकूल वर्षाक्रम के अपेक्षित प्रभाव दिखाई दिए और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमानों को 0.9% कम (पिछले वर्ष के पहले अग्रिम अनुमानों की तुलना में) निर्धारित किया गया. कृषि सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) (2011-12 की कीमतों पर) में वृद्धि दर को भी 1.8% (राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार) और 0.7% (द्वितीय अग्रिम अनुमान) के रूप में कम आंका गया था.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान वर्षा सामान्य से 9% कम हुई और जनवरी-फरवरी 2024 के दौरान सामान्य से 33% कम हुई. नतीजतन, रबी की फसल के मौसम में लगातार अनेक सप्ताह में जलाशयों का जलस्तर कम बना रहा, जिससे रबी की पैदावार की चिंता होने लगी थी. हालांकि, खाद्यान्न उत्पादन (खरीफ और रबी दोनों का संयुक्त रूप से) ने अनुकूलता का प्रदर्शन किया और कृषि वर्ष 2023 के समान ही, कृषि वर्ष 2024 के लिए 328.9 मिलियन टन का उत्पादन (तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) अनुमानित किया गया है (चित्र 1.6).[9] वित्त वर्ष 2024 में बागवानी फसलों का उत्पादन (द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार) 352.2 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की 355.5 मिलियन टन की उपलब्धि की तुलना में मामूली गिरावट दर्शाता है. राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों में, कृषि जीवीए में वृद्धि को 1.4% कर दिया गया था (चित्र 1.5). जलवायु संबंधी झटकों के प्रति भारतीय कृषि के बढ़ते लचीलेपन के साथ कृषि क्षेत्र का जीवीए कुछ वर्षों से निरंतर बढ़ता जा रहा है.

चित्र 1.5: कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीवीए में वृद्धि, 2011-12 के मूल्यों पर (%)

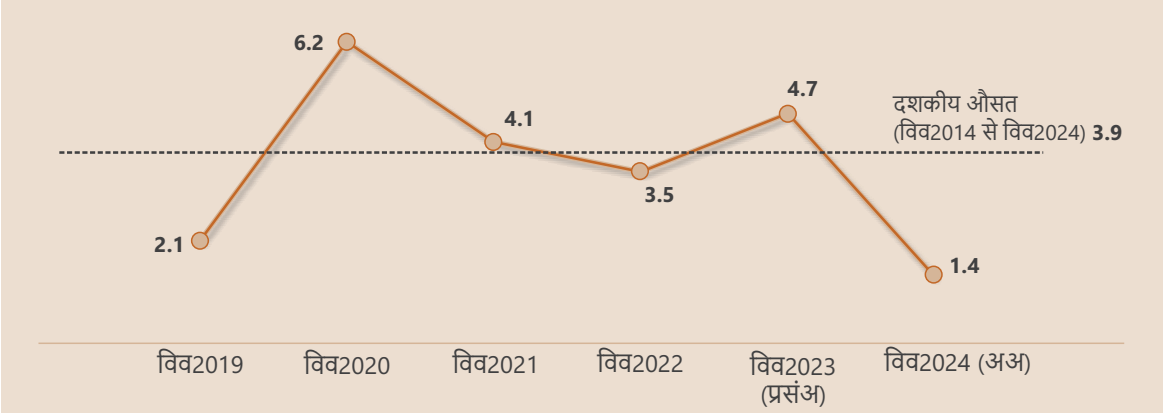

जीवीए = सकल वर्धित मूल्य, पीई = अनंतिम अनुमान.

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.

वित्तीय वर्ष 2023 और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए : पीआईबी (2024), 2023-24 और तिमाही के लिए वार्षिक जीडीपी के अनंतिम अनुमान 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए जीडीपी का अनुमान, पत्र सूचना कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा प्रेस विज्ञप्ति, 31 मई. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?

चित्र 1.6: भारत में खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)

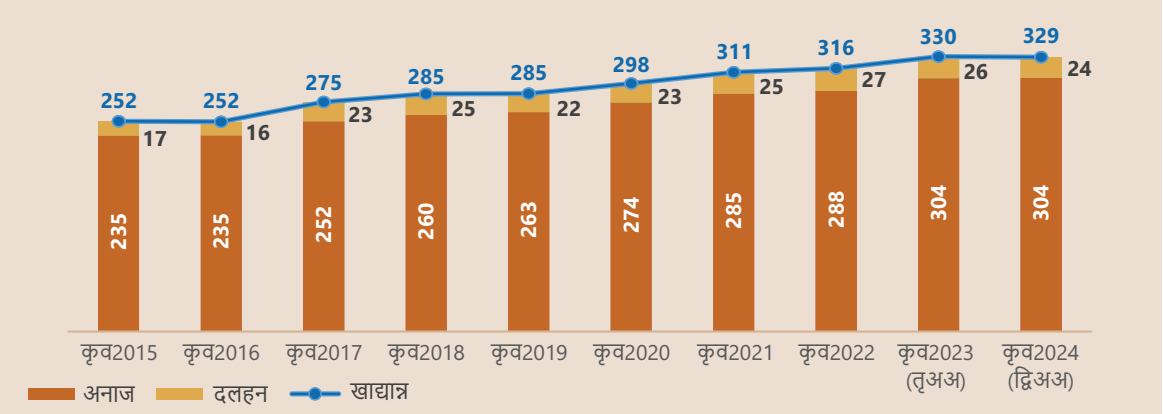

कृव = कृषि वर्ष, एसएई = द्वितीय अग्रिम अनुमान, टीएई = तृतीय अग्रिम अनुमान.

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

1.3.1 परिवारों की उपभोग टोकरी में कम होता खाद्यान्नों का हिस्सा

11 वर्षों के अंतराल के बाद जारी, अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक की अवधि से संबंधित उपभोग व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) के परिणामों ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परिवारों के उपभोग क्रम में एक अलग परिवर्तन दर्शाया है, जिसमें भोजन और विशेष रूप से अनाज की हिस्सेदारी, कुल मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में गिरावट आई है (तालिका 1.2). समग्र स्तर पर, समय के साथ, जैसे-जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, यह उम्मीद की जाती है कि उसकी उपभोग की टोकरी में भोजन का हिस्सा घटेगा, और उसमें भी भोजन के अंतर्गत अनाज से हटकर, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और दूध एवं डेयरी उत्पादों जैसी अधिक प्रोटीन वाली वस्तुओं को अलग स्थान दिया जाने लगेगा है, इसकी तसदीक सीईएस द्वारा की गई है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, दोनों में पानी की अधिक खपत करने वाले खाद्य पदार्थों यथा, अनाज और चीनी के हिस्सों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, यह समय उस अवधि के साथ मेल खाता है जब भारत में पानी की समस्या बढ़ने की सूचना है. उपभोग के क्रम में वांछित बदलावों के बावजूद, पानी की बचत करने वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि जलवायु परिवर्तन के झटकों के प्रति भारतीय कृषि की अनुकूलनशीलता को और अधिक बढ़ाया जा सके. उपभोग के बदलते क्रम से, ऋण के साथ-साथ संसाधनों, जिनकी आगे चलकर मांग बढ़ने की अपेक्षाओं के चलते खाद्यान्नों के उत्पादन को संवर्धित करने की आवश्यकता पड़ सकती है.

तालिका 1.2: औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के प्रतिशत के रूप में अनाजों/ खाद्य पदार्थों का हिस्सा

	ग्रामीण		*शहरी*	
अवधि	*अनाज*	*खाद्य पदार्थ*	*अनाज*	*खाद्य पदार्थ*
विव 2000	22.2	59.4	12.4	48.1
विव 2005	17.5	53.1	9.6	40.5
विव 2010	13.8	57.0	8.2	44.4
विव 2012	10.8	52.9	6.7	42.6
विव 2023	4.9	46.4	3.6	39.2

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.

पानी की बचत करने वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि जलवायु परिवर्तन के झटकों के प्रति भारतीय कृषि की अनुकूलनशीलता को बढ़ाया जा सके.

हाल के वर्षों में, कृषि क्षेत्र को प्रदान किया गया वार्षिक ऋण प्रवाह लगातार लक्ष्यों से अधिक रहा है.

1.3.2 कृषि में मजबूत ऋण प्रवाह

हाल के कुछ वर्षों में कृषि को वार्षिक ऋण प्रवाह निरंतर लक्ष्य से अधिक हुआ है (चित्र 1.7). कृषि के लिए ऋण प्रवाह (वाणिज्यिक बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और सहकारी संस्थानों, सबका मिलाकर) में वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 13.6% की वृद्धि दर्ज हुई, जो कृषि जीवीए में 5.4% की मामूली सी वृद्धि से अधिक थी. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना ने 30 जून 2023 तक की स्थिति के अनुसार 7.4 करोड़ से अधिक के सक्रिय केसीसी खातों के साथ किसानों को समय पर ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें कुल ₹8.9 लाख करोड़ का बकाया ऋण शामिल है.[10]

चित्र 1.7: कृषि को वार्षिक ऋण प्रवाह

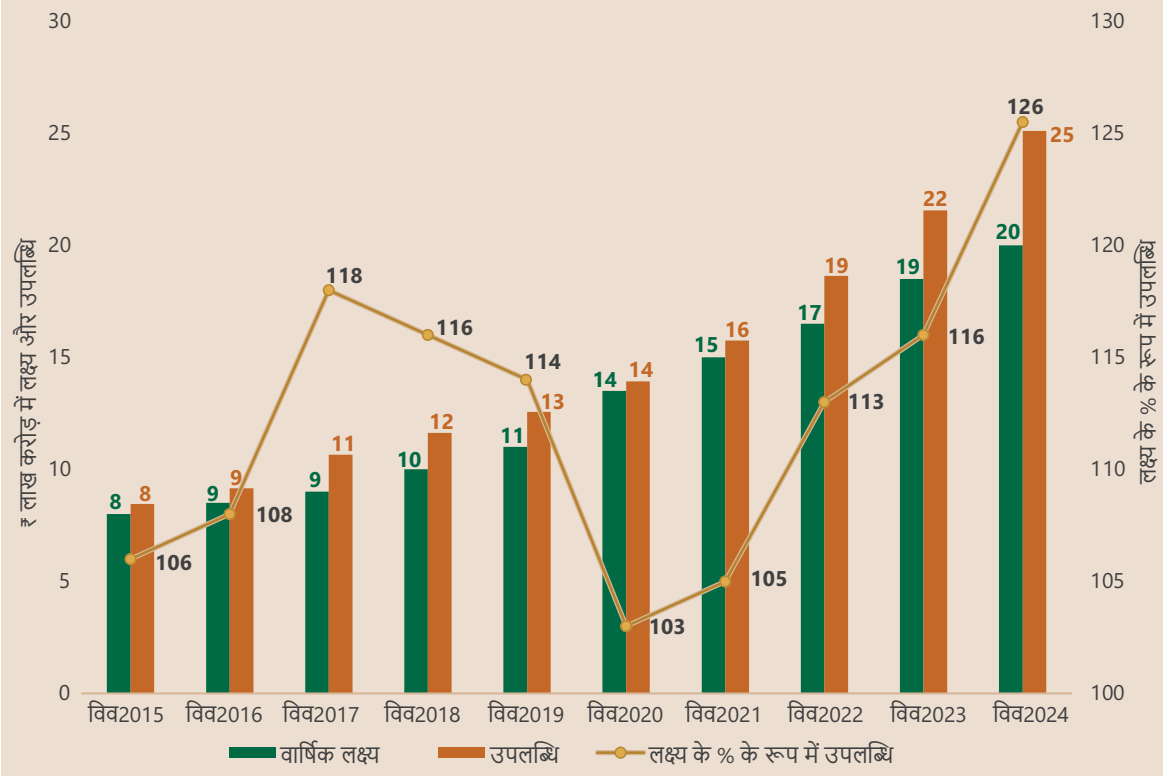

स्रोत:

1. आरबीआई (विभिन्न वर्ष), भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई.
2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक.

1.3.3 प्रतिबंधों के बावजूद कृषि निर्यात यथावत रहा

वित्तीय वर्ष 2022 से भारत का वार्षिक कृषि निर्यात लगभग $50 बिलियन बना हुआ है (चित्र 1.8). फिर भी, निर्यात की टोकरी अत्यधिक रूप से संकेंद्रित ही रही (जिसमें बासमती चावल सहित, चावल का हिस्सा सबसे अधिक था, चावल और चीनी एक साथ मिलकर कुल निर्यात का एक तिहाई से अधिक का हिस्सा थे). मूल्य के दबावों को नियंत्रित करने के लिए घरेलू उपलब्धता में सुधार लाने के उद्देश्य से चावल और चीनी के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान $48.8 बिलियन का कुल कृषि निर्यात हुआ जो वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में मामूली रूप से कम था.

चित्र 1.8: कृषि निर्यात ($ बिलियन)

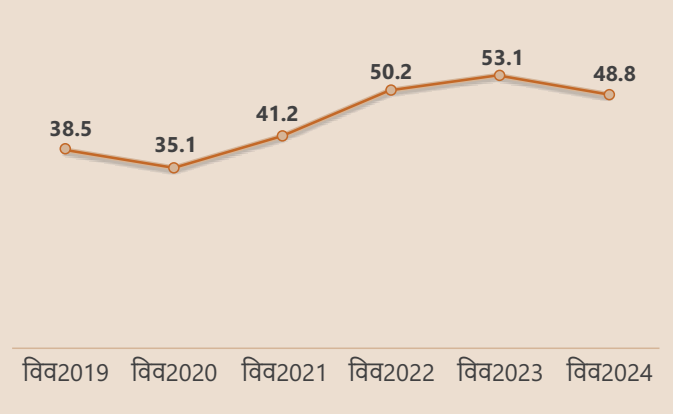

स्रोत: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, भारत सरकार.

1.3.4 अधिक दक्ष कृषि-आपूर्ति शृंखला के लिए नई पहलें

कृषि की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य मुद्रास्फीति की अस्थिरता को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, भारत सरकार द्वारा अनेक नई पहलें आरंभ और संवर्धित की जा रही हैं. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना वर्ष के दौरान शुरू की गई, जिससे देश की खाद्यान्न भंडारण क्षमता में और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है. इससे फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी, किसानों द्वारा फसलों की गरजू बिक्री को रोका जा सकेगा और उन्हें बाद में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकेगा. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के अधिप्राप्ति केंद्रों के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों के आपूर्ति स्रोतों के रूप में काम करने से परिवहन पर होने वाली लागत को बचाया जा सकेगा.

सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, पैक्स के संबंध में चल रहे महत्वाकांक्षी कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रमों के साथ-साथ अगले 5 वर्षों में 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स/ डेयरी/ मत्स्य प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है.[11] गैस/ पेट्रोल के खुदरा वितरण, कस्टम हायरिंग केन्द्रों, उचित मूल्य की दुकानों, गोदामों आदि जैसे क्षेत्रों में पैक्स के व्यापार को विविधीकृत करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं. साथ ही निर्यात, प्रमाणित बीज और जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना की मंजूरी दी गई है.

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 144 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से 17.7 करोड़ परिवारों को बचत से जोड़ा गया जिसमें ₹65,089.2 करोड़ से अधिक की जमाराशियां और ₹2,59,663.7 लाख करोड़ से अधिक का ऋण शामिल है.[12] ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को स्थायी आधार पर ₹1 लाख से अधिक वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए 'लखपति दीदी' नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है.

इससे पहले भारत सरकार ने, यह मानते हुए कि कृषक उत्पादक संगठन सामूहिकीकरण के माध्यम से किसानों की मोल-भाव की शक्ति बढ़ाकर निविष्टियों तक पहुँच में सुधार और अपनी उपज के लिये अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में उन्हें सक्षम बना सकते हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है, '10,000 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन' के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की थी. अब तक, देश भर में 7,355 एफपीओ को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 6,056 एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं, जो गुणवत्तापूर्ण निविष्टियों की आपूर्ति, सदस्यों के लिए कस्टम हायरिंग आधार पर मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराने और कृषि उपज की सफाई, परख, छंटाई, ग्रेडिंग और प्रसंस्करण जैसे मूल्य वर्धन कार्यों, जैसी विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं.[13] इन सभी पहलों से वित्तीय समावेशन की पैठ अधिक गहरी करने, आजीविका के नए अवसर पैदा करने, आय में वृद्धि करने और कृषि-प्रौद्योगिकी समाधानों तक पहुंच बढ़ने की उम्मीद है.

विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना (डब्ल्यूएलजीएसपी) से फसलोपरांत हानि कम होगी, फसलों की गरजू बिक्री रुकेगी और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा.

सरकार ने कृषि में अनेक प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेप किए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, नमो ड्रोन दीदी और डेटा-संचालित समाधानों की शुरुआत को सक्षम बनाने के लिए एग्री स्टैक आर्किटेक्चर शामिल है.

कृषि स्टार्ट-अप, कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की अगुआई में रूपांतरकारी परिवर्तनों को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके महत्व को पहचानते हुए, नीतिगत वातावरण को उनके लिए अनुकूल बनाया गया है. दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 590 से अधिक जिलों में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त 6,000 से अधिक कृषि स्टार्ट-अप थे.[14] कृषि क्षेत्र में पहले से चले आ रहे और नए उभरते, दोनों तरह के मुद्दों के समाधान के लिए निजी क्षेत्र की बड़े पैमाने पर भागीदारी ज़रूरी है. कई स्टार्ट-अप किफायती और बहुउद्देश्यीय ड्रोन विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं जिनका उपयोग कम समय में खेत की खोज-खबर लेने और निर्धारित नक्शे और योजनाएं जनरेट करने और प्राकृतिक आपदा के बाद फसल क्षति का आकलन करने के लिए सटीक डेटा कैप्चर करने हेतु किया जा सकता है. इसी प्रकार, बागवानी और डेयरी उत्पादों, जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, की बर्बादी को कम करने के लिए पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज उपकरणों का पता लगाया जा रहा है. कई स्टार्ट-अप फसल अवशेषों (पराली) के जलाए जाने, जिससे प्रदूषण होता है, की समस्या से निपटने के लिए किफायती समाधान खोजने पर काम कर रहे हैं. कई अभिनव उत्पाद अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में हैं तथा उन्हें निवेशकों और सरकारों से सहारे की आवश्यकता है ताकि उनका सफल परीक्षण हो सके और अर्थव्यवस्था पर वांछनीय सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उन्हें स्केल-अप किया जा सके. सरकार द्वारा भी अनेक प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेप किए गए हैं, जिनमें विभिन्न कारणों से पैदावार के संभावित नुकसान से निपटने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग-आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली शामिल है, जैसे कि कीटों के हमले या मौसम के पैटर्न में अप्रत्याशित परिवर्तन; खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करके कृषि में ड्रोन तकनीक को अपनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना; और विभिन्न हितधारकों द्वारा डेटा-संचालित समाधानों की शुरुआत को सक्षम बनाने के लिए एक एग्री स्टैक आर्किटेक्चर का विकास.

1.4 ग्रामीण आर्थिक गतिविधि में आई गति

एक मजबूत, वैविध्यपूर्ण और समावेशी विकास की प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है.[15] महामारी के बाद की अवधि में, ग्रामीण आर्थिक संकेतकों ने यह पता लगाने में सहायता की है कि अर्थव्यवस्था का यह महत्वपूर्ण खंड कैसे बहाल हुआ, और उपलब्ध जानकारी वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान विकास की गति को संधारणीय रूप से सदृढ़ करने के संकेत देती है.

चित्र 1.9: ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई)

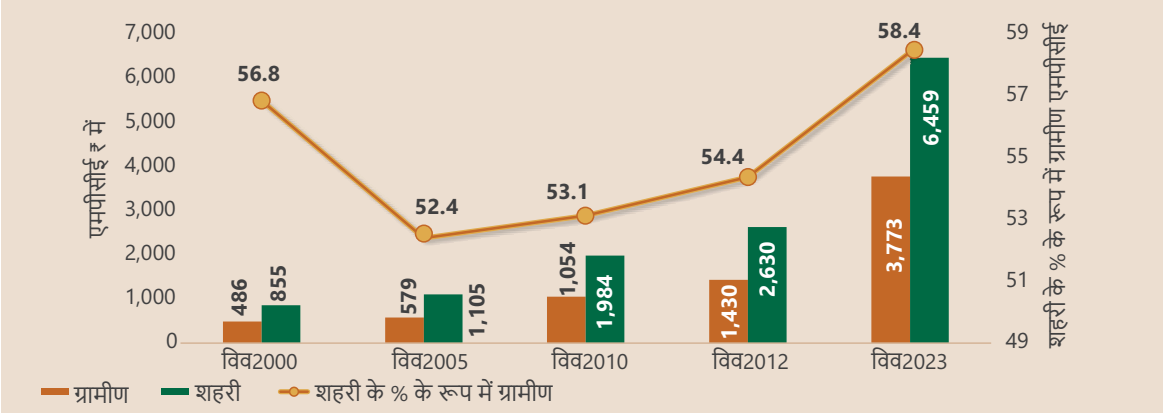

एमपीसीई = मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय

स्रोत: भारत सरकार (विभिन्न वर्ष), घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2022-23), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. .

1.4.1 ग्रामीण-शहरी उपभोग के बीच अंतर हुआ कम

समय के साथ मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में परिवर्तन, आर्थिक प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक होता है. वित्तीय वर्ष 2023 के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एमपीसीई में अंतर कम हुआ है, शहरी व्यय में ग्रामीण व्यय का प्रतिशत 58.4 रहा, जो वित्तीय वर्ष 2012 में 54.4% था (चित्र 1.9). और तो और, ग्रामीण व्यय ने शहरी परिवारों के 8.5% की तुलना में 9.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की.[16]

1.4.2 ग्रामीण बेरोज़गारी की दर में गिरावट जारी रही

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए बेरोज़गारी एक और प्रमुख संकेतक होता है. वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की दर 2.4% थी, जो शहरी क्षेत्रों में 5.4% थी, और वित्तीय वर्ष 2018 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोज़गारी में भी लगातार गिरावट आई है (चित्र 1.10). यह गिरावट, महत्वपूर्ण रूप से, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में सतत् वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में हुई है, यानी, जनसंख्या में श्रम बल (काम कर रहे या काम की तलाश कर रहे या काम के लिए उपलब्ध) में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि (चित्र 1.10).

चित्र 1.10: बेरोज़गारी की दर (%) और श्रम बल भागीदारी की दरें (%) (वित्तीय वर्ष 2018–वित्तीय वर्ष 2023)

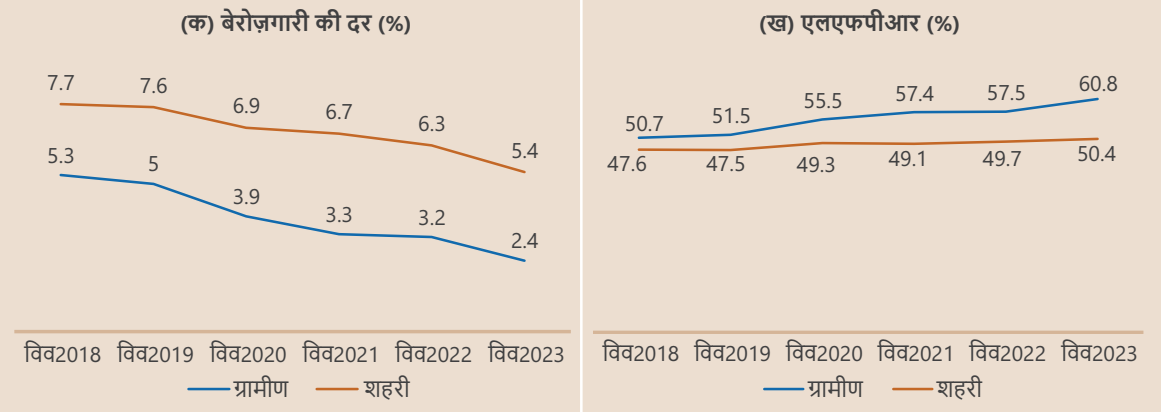

एलएफपीआर = श्रम बल भागीदारी दर.

स्रोत: भारत सरकार (विभिन्न वर्ष), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.

1.4.3 ग्रामीण गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक सुदृढ़ हुए

उच्च-आवृत्ति (मासिक) वाले अनेक संकेतक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने में सहायता करते हैं, जैसे स्कूटरों की बिक्री, उर्वरकों और ट्रैक्टरों की बिक्री, कृषि और गैर-कृषि रोज़गार, कृषि निर्यात, कृषि में बैंक ऋण प्रवाह, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत काम की मांग, ग्रामीण मजदूरी, व्यापार की शर्तें (यानी, खाद्य कीमतों और गैर-खाद्य कीमतों का अनुपात, जैसा कि थोक मूल्य सूचकांक से प्राप्त होता है), जलाशयों का स्तर (जो फसलों की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है), और ग्रामीण भावनाएं.[17] संकेतकों की तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए, सभी सामान्य संकेतक (जैसे कृषि निर्यात, कृषि ऋण और ग्रामीण मजदूरी) उपभोक्ता मूल्य संकेतक-ग्रामीण मुद्रास्फीति द्वारा अपस्फीत (डीफ्लेट) हो जाते हैं. इन संकेतकों में मौसम के मजबूत प्रभाव को स्वीकार करते हुए, पिछले वर्ष के संबंध में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के उचित मूल्यांकन के लिए, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 12 माह की अवधि में इन संकेतकों के औसत मूल्यों की तुलना वित्तीय वर्ष 2023 की इसी अवधि के दौरान के संबंधित मूल्यों के

हाल के वर्षों में ग्रामीण-शहरी उपभोग का अंतर कम हुआ है, ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आई है और ग्रामीण आर्थिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतकों में सुधार हुआ है.

समक्ष की जा सकती है. इस तरह की तुलना से यह पता चलता है कि अधिकांश संकेतकों का विस्तार हुआ है. अत:, कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान ग्रामीण गतिविधि ने गति पकड़ी है.

चित्र 1.11: ग्रामीण गतिविधि संकेतक (वित्तीय वर्ष 2023 के मासिक औसतों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 के मासिक औसतों में परिवर्तन)

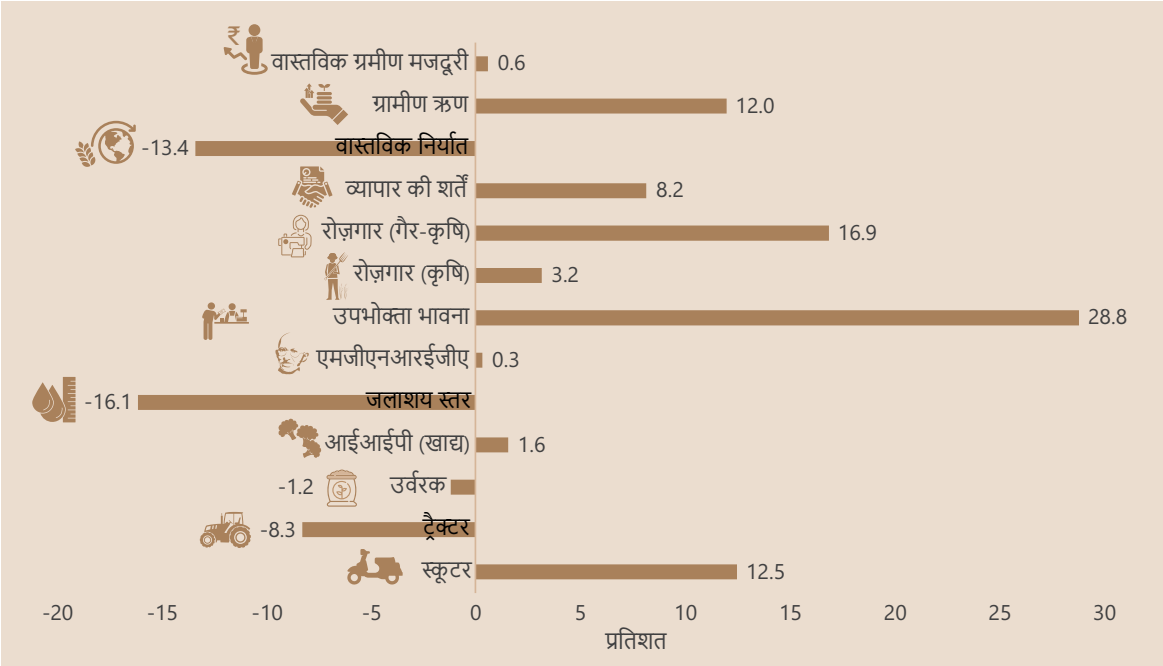

आईआईपी = औद्योगिक उत्पादक सूचकांक, एमजीएनआरईजीए = महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम.

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार; और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी.

1.4.4 बहुआयामी नीतिगत हस्तक्षेपों से प्रभावशाली ग्रामीण विकास उपलब्धियां

सरकार द्वारा विकास के प्रति अपनाए जा रहे बहुआयामी दृष्टिकोण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी लाभ हुए हैं, जिनमें सभी के लिए सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा, आवासन, पेयजल, बिजली, रसोई गैस, बैंक खाते और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं. जैसा कि अंतरिम बजट 2024-25 में घोषणा की गई है, प्रधान मंत्री (पीएम) आवास योजना (ग्रामीण) 3 करोड़ घरों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है, अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे. रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा. लक्ष्योन्मुखी नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव को दर्शाते हुए, पीएम-स्वनिधि ने 78 लाख फेरीवालों को ऋण सहायता प्रदान की है; पीएम विश्वकर्मा योजना ने 18 वृत्तियों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को आद्योपांत सहायता प्रदान करती है; प्रधान मंत्री (पीएम) - किसान सम्मान निधि के तहत, 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है; और राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई नाम) ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है.[18]

सरकार के बहुआयामी विकास दृष्टिकोण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रूपांतरकारी परिवर्तन हुए हैं.

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), जो एक मांग आधारित, नियोजन से जुड़ी कौशल प्रशिक्षण पहल है, के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को 3 से 12 महीनों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. 31 मार्च 2024 तक लगभग 15.8 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 9.6 लाख को नौकरी मिल चुकी है.[19]

जल जीवन मिशन ने सभी घरों के लिए नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य के साथ-साथ, स्थानीय जल संसाधनों के समग्र प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिसके तहत स्थानीय पंचायतों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है. मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर (तालाबों) अर्थात् देश में कुल लगभग 50,000 तालाबों का विकास/ पुनरुज्जीवन करना है. प्रारंभिक लक्ष्य को पार करते हुए, दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार, 1.1 लाख स्थानों की पहचान की गई और 68,187 स्थानों में काम पूरा किया गया.[20]

मिशन अमृत सरोवर ने भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवरों को विकसित किया है.

पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 (पीएमयूवाई) ने 8 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था, जिसे सितंबर 2019 में ही प्राप्त कर लिया गया था. शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, अधिक कनेक्शन दिए जाने शुरू किए गए थे. 1 जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार, लगभग 9.6 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थी थे, जिनमें से 8.4 करोड़ ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान कम से कम एक रीफिल लिया था. इस योजना को 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने के वित्तीय वर्ष 2024 और वित्तीय वर्ष 2026 के बीच तक के लिए बढ़ाया गया है, जिससे पीएमयूवाई लाभार्थियों की कुल संख्या 10.4 करोड़ हो जाएगी.[21]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने हेतु एक रूपांतरकारी नीति रही है. दिसंबर 2023 तक,

- 8.2 लाख किलोमीटर लंबाई की 1.9 लाख सड़कों और 11,587 पुलों को मंजूरी दी गई है, जिनका कुल मूल्य ₹3.8 लाख करोड़ है;
- पीएमजीएसवाई-I के तहत, 99.4% पात्र बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया जा चुका है;
- पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 49,857 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गईं और 48,691 किलोमीटर का कार्य पूरा किया जा चुका है.
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना के अंतर्गत 12,100 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई और 8,290 किलोमीटर का कार्य पूरा किया जा चुका है; और
- पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत 13 लाख किलोमीटर सड़कों के लक्ष्य की तुलना में 11 लाख किलोमीटर लंबाई को मंजूरी दी गई और 69,507 किलोमीटर का कार्य पूरा किया जा चुका है.[22]

पीएम सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के शुभारंभ से, 2.9 करोड़ घरों (आदिवासी घरों सहित) का विद्युतीकरण किया गया, जिससे 100% विद्युतीकरण पूरा हुआ. भारत सरकार ने बिजली वितरण प्रणालियों को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की थी जिसके अंतर्गत कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना; उप-पारेषण और वितरण की आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन करना; वितरण ट्रांसफार्मर/ फीडर/ उपभोक्ताओं की मीटरिंग करना; और देश भर के गांवों का विद्युतीकरण करना शामिल है. जैसा कि राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, भारत की जनगणना 2011 में उल्लिखित सभी बसे हुए गैर-विद्युतीकृत गांवों को डीडीयूजीजेवाई के तहत 28 अप्रैल 2018 तक विद्युतीकृत किया जा चुका है. इस योजना के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया.[23]

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) को केंद्रीय और राज्य एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और स्वायत्त निकायों सहित सभी सरकारी खरीदारों द्वारा माल और सेवाओं की खरीद के लिए वन-स्टॉप राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में संवर्धित किया गया है. उद्यम-सत्यापित सूक्ष्म और लघु उद्यम अब, जेम में किए गए कुल संचयी लेन-देन के सकल बाज़ार मूल्य का लगभग आधा हिस्सा बन गए हैं, और महिला उद्यमियों, कारीगरों और बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों, खादी उत्पादकों आदि तक इसकी पहुंच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, जेम के तहत 'एक-जिला एक-उत्पाद' योजना को लोकप्रिय बनाया जा रहा है.

महिला उद्यमियों, कारीगरों और बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), खादी उत्पादकों आदि की पहुँच को बढ़ाने के लिए, 'एक जिला एक उत्पाद' योजना को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के तहत लोकप्रिय बनाया जा रहा है

संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण की प्रगति का अनुप्रवर्तन करने, जो संधारणीय विकास लक्ष्यों पर 2030 तक के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) तैयार किया गया था. एक बहुआयामी सूचकांक के रूप में, पीडीआई पोर्टल के माध्यम से गुणवत्तात्मक डेटा रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

1.5 आर्थिक दृष्टिकोण

वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के पुन:संरेखण ने कम लागत वाले उत्पादन के संभावित विश्वसनीय स्रोत के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ाया है.

भारत के मजबूत व्यापक नीतिगत वातावरण और पूर्व के सुधारों के संभावित लाभों की प्राप्ति ने विकास के दृष्टिकोण को प्रकाशमान किया है, जैसा कि भारत के विकास अनुमानों में लगातार ऊर्ध्वगामी संशोधनों, एक फलते-फूलते शेयर बाज़ार और मजबूत ऋण मांग से स्पष्ट होता है. सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय से विकास के लिए निरंतर सहयोग और मौजूदा उत्पादन क्षमताओं के उच्चतर उपयोग के साथ, निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी आने की उम्मीद है. ग्रामीण मांग में सुधार के चलते, उपभोग मांग की गति भी वैविध्यपूर्ण हो रही है. राजकोषीय समेकन की गति (जो बाजारों की उम्मीदों से भी अधिक तेज़ है) और प्रक्रियाओं को बनाए रखने की प्रतिबद्धता ने निजी क्षेत्र के लिए, पूंजी की लागत पर दबाव को कम कर दिया है. मुद्रास्फीति में कमी और मुद्रास्फीति को लक्ष्य के करीब लाने और मुद्रास्फीति की आशंकाओं पर रोक लगाने के लिए मौद्रिक नीति पर बल देने से भी मुद्रास्फीति जोखिम प्रीमियम को नियंत्रित करने में सहायता मिली है. कॉरपोरेटों और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के स्वस्थ तुलन-पत्रों ने जोखिम से बचने में मदद की है.

14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए लक्ष्योन्मुखी उत्पादन-युक्त प्रोत्साहन योजना; लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार पर नीतिगत बल; और नवीकरणीयों, सेमीकंडक्टरों और डिजिटलीकरण में विद्यमान अवसरों का लाभ उठाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण ने अर्थव्यवस्था में विकास की अंतर्निहित शक्तियों को और सशक्त किया है. प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के बावजूद, सेवा क्षेत्र निर्यात में उछाल बना हुआ है और भू-राजनीतिक कारकों द्वारा संचालित वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के पुन:संरेखण ने वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए कम लागत वाले उत्पादन के संभावित विश्वसनीय स्रोत के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ा है. इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 7.2% की विकास-दर अनुमानित की गई है, जो अगर प्राप्त कर ली जाती है, तो भारत लगातार चौथे वर्ष के लिए 7% से अधिक की वृद्धि-दर प्राप्त करने वाला देश बन जाएगा.[24] एक ओर जहां, घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति नरम हुई है, और महत्वपूर्ण रूप से मूल मुद्रास्फीति भी 4% से नीचे गिर गई है,[25] वहीं दूसरी ओर, भू-राजनीतिक कारकों से तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर ऊर्ध्वगामी दबाव डालने वाले अपसाइड रिस्क और मौसम-संबंधी गड़बड़ियां खाद्यान्नों की कीमतों को उल्लेखनीय रूप से कम होने से रोक रही हैं. अत:, मुद्रास्फीति से लड़ाई का अंतिम पड़ाव भारतीय और वैश्विक स्तर, दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती होने की उम्मीद है, जो भविष्य की नीतिगत दर के रुझानों के लगातार पुनर्मूल्यांकन के कारण बाजारों को अस्थिर रख सकता है.

भारतीय कृषि ने जलवायु जनित घटनाओं के प्रति अधिक अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन किया, किंतु मौसम की लगातार गड़बड़ियों के कारण, कृषि जीवीए की वृद्धि में गिरावट आई और खाद्यान्न उत्पादन स्थिर रहा. कृषि क्षेत्र की संरचनात्मक बाधाएं हटाने की सुस्त गति भारत के आगे बढ़ने की राह में विकास और मुद्रास्फीति दोनों स्तरों पर विपरीत जोखिम पैदा कर सकती है, जब तक कि इनका समाधान समय पर नहीं कर लिया जाता है तो जलवायु परिवर्तन से इन समस्याओं में और वृद्धि ही होगी. उर्वरकों, कीटनाशकों, पानी, बिजली और भूमि के आदानों-संसाधनों के संधारणीय उपयोग के साथ फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम फसलीय पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता होगी, जो कि भारत में तब तक कठिन होगा जब तक रोज़गार के लिए कृषि पर अधिक निर्भरता, जो आज भी है, वह कम नहीं होती और सब्सिडी को कम करने और कृषि में पूंजी के निर्माण को बढ़ाने के माध्यम से संसाधनों का पुन:आबंटन नहीं किया जाता है.

भारत@2047 की खाद्य सुरक्षा और विकासपरक चुनौतियों से निपटने के लिए नवोन्मेषी एग्रिटेक का व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक है.

जहां कृषि-स्टार्ट-अप भारतीय कृषि में एक वांछित तकनीक-आधारित परिवर्तन ला रहे हैं–बुआई से लेकर कटाई, भंडारण और खुदरा विपणन तक–वहीं उभरते वैश्विक रुझानों को पहचानते हुए, खाद्य सुरक्षा और भारत@2047 की विकासपरक चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारत में इस तरह की अभिनव पद्धतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार अत्यावश्यक हो जाएगा. वित्तीय वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में 'कृषि उत्पादकता और लचीलेपन में सुधार' को प्राथमिकता के रूप में रखने और भारत में कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है (बॉक्स 1.1). कृषि में श्रम उत्पादकता (यानी, प्रति इकाई श्रम का प्रतिफल) भारत में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में और समग्र देश के संदर्भ में कम रही है. कृषि में अपर्याप्त निवेश ने भारत की फसल पैदावार को अन्य प्रमुख उत्पादक देशों की उच्चस्तरीय पैदावार के साथ बराबरी करने से रोका है. उपज के इस अंतर को दूर करने के लिए, कृषि में पूंजी और प्रौद्योगिकी की तीव्रता को बढ़ना ही होगा, चाहे छोटी और मध्यम भू-जोतों के एक बड़े हिस्से और रोजगार के लिए कृषि पर उच्च निर्भरता से उत्पन्न चुनौती ही क्यों न हो, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है. कृषि आय और मजदूरी ग्रामीण आय के दो प्रमुख स्रोत हैं; जहां अधिक पैदावार किसानों की वास्तविक आय बढ़ा सकती है, वहीं उत्पादकता से जुड़ी मजदूरी वास्तविक समृद्धि ला सकती है. अन्यथा, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और उसके परिणामस्वरूप ग्रामीण मजदूरी में अधिक कमी केवल मजदूरी और मूल्य के बीच एक विषम चक्र निर्मित

होने का कारण ही बन सकती है, जो व्यापक आर्थिक परिदृश्य के लिए हानिकारक हो सकता है. कृषि की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, अधिकाधिक निजी निवेश, घरेलू और विदेशी दोनों, को आकर्षित करने के लिए, कृषि में निवेश पर प्रतिफल के बारे में अनिश्चितता, जो बार-बार व्यापार नीति में परिवर्तनों और बाज़ार मूल्यों को प्रभावित करने वाले हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप होती है, का आकलन किया जाए और जहां तक संभव हो उनसे बचा जाए. कम भूमि और कम निविष्टियों के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त करना, जो अन्य देशों के अनुभवों के अनुसार संभव है, उपभोक्ताओं के लिए खाद्य पदार्थों की कीमतों को यथोचित रखते हुए किसानों की आय बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग है.

बॉक्स 1.1: केंद्रीय बजट 2024-25 - मुख्य बातें

- कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने और इसमें मजबूती लाने के लिए चुने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: (क) कृषि अनुसंधान का रूपांतरण (ख) नई किस्में जारी करना (ग) प्राकृतिक खेती (घ) दलहन और तिलहन हेतु मिशन (ङ) सब्जी उत्पादन और आपूर्ति शृंखला (च) कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत संरचना (छ) झींगा (श्रिम्प) उत्पादन और निर्यात.
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹1.52 लाख करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ की राशि आबंटित की गई है.
- किसानों हेतु खेती के लिए, 32 अधिक उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की जाएंगी.
- उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ निविष्टि लागत को कम करने की दृष्टि से अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा, 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-निविष्टि संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
- सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए, बजट में, खपत के प्रमुख केंद्रों के निकट बड़ी क्षमता वाले उत्पादन क्लस्टरों के सृजन का प्रस्ताव है. इन क्लस्टरों का उद्देश्य होगा सब्जी उत्पादन और वितरण की दक्षता को बढ़ाना.
- बजट डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत संरचना को विकसित करने पर केंद्रित है, जिसके तहत 400 जिलों में खरीफ की फसलों के लिए एक डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा. यह सर्वेक्षण छह करोड़ किसानों के डेटा को राष्ट्रीय रजिस्ट्रियों के साथ जोड़ेगा, जिससे कृषि सेवाओं तक पहुँच सुव्यवस्थित होगी.
- श्रिम्प ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसके तरहत श्रिम्प पालन और निर्यात के वित्तपोषण की सुविधा नाबार्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी. इस पहल से श्रिम्प पालन उद्योग और उसके निर्यात क्षमता बढ़ने की उम्मीद है.
- जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा.
- ग्रामीण विकास के संवर्धन के लिए सहकारी संरचना में सुधार - सरकार सहकारी क्षेत्र के सुनियोजित, व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाएगी.
- कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, इस बजट में महिला-विशिष्ट कौशल कार्यक्रम आयोजित करने और महिला एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार पहुँच बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है.

नोट्स

1. कैलेंडर वर्ष से पहले विव लगाने से आशय वित्तीय वर्ष या वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली 12 माह की अवधि से है. उदाहरण के लिए, विव 2024, 1 अप्रैल 2023 –31 मार्च 2024 की अवधि को दर्शाता है.
2. आईएमएफ (2024), वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रका कोष, जनवरी. https://www.imf.org/external/Pubs/FT/weo/2024/01/pdf/January%202024%20WEO%20Update_EN.pdf.
3. यूएनसीटीएडी (2024), वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, यूएन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट, जेनीवा. https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024.

4. भारत सरकार (2024क), राष्ट्रीय आय 2023-24 का दूसरा अग्रिम अनुमान, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.
5. भारत सरकार (2024ख), केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार| आरबीआई (2024), मुद्रा नीति विवरण (2023-24), भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई.
6. आरबीआई (2023), राज्य वित्त: बजट अध्ययन, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई.
7. आरबीआई, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई. https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home.
8. आईएमडी (2023), 2023 दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम समाप्ति रिपोर्ट, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार.
9. कैलेंडर वर्ष से पहले एवाई लगाने से आशय कृषि वर्ष या वर्ष के 30 जून को समाप्त होने वाली 12-माह की अवधि से है. उदाहरण के लिए, कृषि वर्ष 2023, 1 जुलाई 2022-30 जून 2023 की अवधि को दर्शाता है.
10. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय.
11. पीआईबी (2023क), 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक व्यापक बनाने को मंजूरी दी', पत्र सूचना ब्यूरो. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी 2023 को पोस्ट की गई प्रेस विज्ञप्ति. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1899445.
12. नाबार्ड (2023), भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थिति 2022-23, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई. https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/status-of-microfinance-in-india-2022-23.pdf.
13. पीआईबी (2023ख), 'कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना', पत्र सूचना ब्यूरो. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई 2023 को पोस्ट की गई प्रेस विज्ञप्ति. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1942484.
14. भारत सरकार (2023क), स्टार्टअप इंडिया, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार. https://www.startupindia.gov.in/nsa2023results/assets/File/NSA_NationalReport.pdf.
15. पीआईबी (2023ग), 'आर्थिक समीक्षा में ग्रामीण विकास की प्राथमिकता को रेखांकित किया गया', पत्र सूचना कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 2023 को पोस्ट की गई प्रेस विज्ञप्ति. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1894901
16. भारत सरकार (2023ख), पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2022-23), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.
17. https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=warticle&dt=20231204145930&msec=896.
18. भारत सरकार (2024ग), केंद्रीय अंतरिम बजट, 2024-25, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.
19. डीडीयू-जीकेवाई वेबसाइट (http://ddugky.info/).
20. मिशन अमृत सरोवर (https://amritsarovar.gov.in/login).
21. पीआईबी (2023घ), 'उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंत्रिमंडल की मंजूरी', पत्र सूचना कार्यालय. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 13 सितंबर 2023 को पोस्ट की गई प्रेस विज्ञप्ति. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1957091.
22. पीआईबी (2023ङ), 'ग्रामीण सड़कों और अमृत सरोवरों का निर्माण', पत्र सूचना कार्यालय. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2023 को पोस्ट की गई प्रेस विज्ञप्ति.https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988662.
23. पीआईबी (2023च), 'सौभाग्य और आरडीएसएस योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण का कार्यान्वयन', पत्र सूचना कार्यालय. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2023 को पोस्ट की गई प्रेस विज्ञप्ति. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1989801.
24. भारतीय रिज़र्व बैंक (2024), नोट 5.
25. भारतीय रिज़र्व बैंक (2024), नोट 5.

अध्याय 1 का परिशिष्ट

चित्र अ1.1: वार्षिक दूध उत्पादन (मिलियन टन) और वार्षिक वृद्धि दर (%)

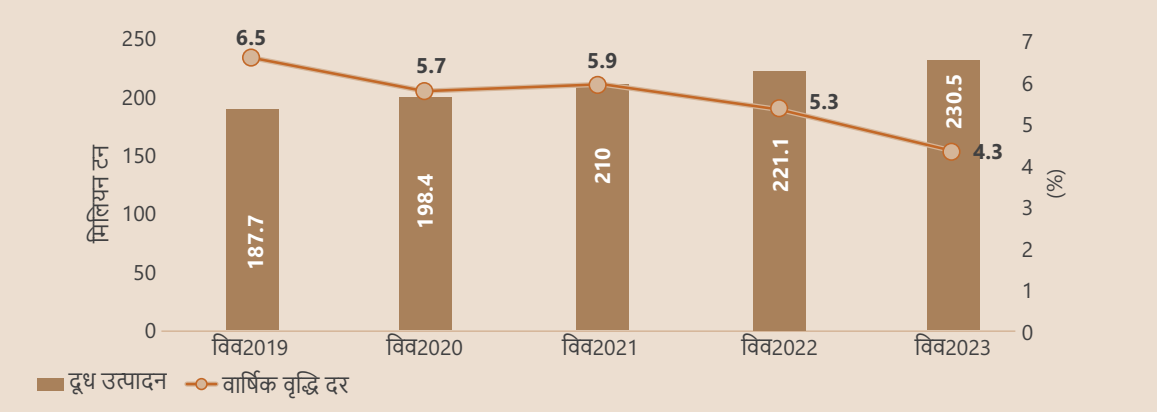

स्रोत: भारत सरकार (2024), वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार.

चित्र अ1.2: भारत में वाणिज्यिक फसल उत्पादन

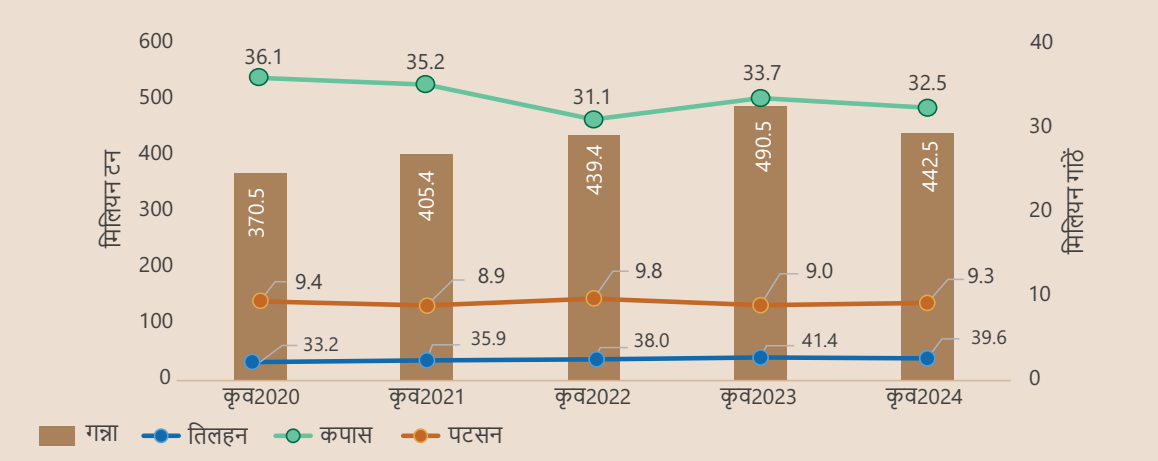

नोट:

- तिलहन और गन्ने को बाँईं ओर वाई-अक्ष पर मिलियन टन में मापा गया है; प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन गांठों में बीटी कपास और दाएँ वाई-अक्ष पर प्रत्येक 180 किलोग्राम की मिलियन गांठों में पटसन.
- कृषि वर्ष 2024 के लिए आंकड़े तृतीय अग्रिम अनुमान हैं.

स्रोत: भारत सरकार (2024), 2023-24 के लिए वाणिज्यक फसल उत्पादन के तृतीय अग्रिम अनुमान, कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. https://desagri.gov.in/wp-content/uploads/2024/06/English.pdf. पृष्ठ 3.

तालिका अ1.1: टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन (मिलियन टन)

वर्ष	*सब्जियाँ*	*बागवानी*	*टमाटर*	*प्याज*	*आलू*
कृषि वर्ष 2020	188.1	320.5	21.2	26.1	48.6
कृषि वर्ष 2021	200.0	334.6	21.2	26.6	56.2
कृषि वर्ष 2022	209.1	347.2	20.7	31.7	56.2
कृषि वर्ष 2023	212.6	355.5	20.6	31.0	59.7
कृषि वर्ष 2024	205.0	352.2	21.2	24.2	56.7

स्रोत: भारत सरकार (2024), 2023-24 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2022761.